



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1029]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2006/भाद्र 22, 1928

No. 1029]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2006/BHADRA 22, 1928

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2006

का.आ. 1488(अ).—संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, नई दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस फेडरेशन एवं रेड क्रीसेंट सोसाइटीज का क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल (जिसे इसके पश्चात् “प्रतिनिधिमंडल” अथवा “क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल” कहा गया है) को एतद्वारा निम्नलिखित विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान करती है :

1. क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल का अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए, जिसमें कि भारत में लागू कानूनों के तहत मुकदमा करने और अपने ऊपर मुकदमा चलाए जाने के अधिकारों सहित, आवश्यक विधिक स्वरूप तथा विधिक क्षमता होगा।
2. क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल तथा उसके सदस्यों को विधिक स्तर मंजूर किए जाने पर राष्ट्रीयता का भेदभाव किये बिना निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा:

 - (i) उनके द्वारा सरकारी तौर पर उच्चरित अथवा लिखित शब्दों तथा किए गए सभी कृत्यों के संबंध में किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई से उन्हें उन्मुक्ति होगी।
 - (ii) अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास फेडरेशन तथा रेड क्रीसेंट सोसायटीज द्वारा उन्हें भुगतान किया गया वेतन तथा परिलिक्षियों के संबंध में कराधान से उन्मुक्ति होगी।
 - (iii) उन्हें राष्ट्रीय सेवा की बाध्यताओं से उन्मुक्ति होगी।
 - (iv) वे अपने / अपनी पति/पत्नी तथा नजदीकी परिवार के सदस्यों के साथ निःशुल्क समुचित प्रवेश वीजा के हकदार होंगे।
 - (v) उन्हें अपने/ अपनी पति / पत्नी तथा उन पर आश्रित संबंधियों के साथ दूसरे देश में पंजीकरण कराए जाने से उन्मुक्ति होगी।

(vi) उन्हें आदान-प्रदान की सुविधाओं के संबंध में वही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो कि सरकार के राजनयिक मिशन का भाग बनने वाले समतुल्य रैंक के अधिकारियों को प्रदान की जाती हैं।

(vii) उन्हें अपने /अपनी पति / पत्नी तथा उन पर आश्रित संबंधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संकटकाल में वही प्रत्यावर्तन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो राजनयिक दूतों को प्रदान की जाती हैं।

3. क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल में कार्य कर रहे भारतीय राष्ट्रिक अथवा भारत के स्थायी निवासीगण किसी प्रकार की उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों के पात्र नहीं होंगे।

4. क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपने आधिकारिक उपयोग के लिए समुचित मात्रा में आयातित सामानों के संबंध में क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल की आस्तियां तथा अन्य संपत्ति यथास्थिति सीमा-शुल्क तथा निषेधों एवं प्रतिबंधों, से छूट प्राप्त होंगी। ऐसी छूट के अंतर्गत अनुयायित सामान, भारत सरकार द्वारा सहमत शर्तों के सिवाए भारत में नहीं बेचे जाएंगे।

5. क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल, सामान्य नियम के तौर पर चल तथा अचल संपत्ति की खरीद पर वैसे उत्पाद शुल्क अथवा करों से छूट प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा आधिकारिक प्रयोग हेतु संपत्ति की खरीद करते समय शुल्क तथा कर प्रभारित किए गए हों अथवा प्रभारित किए जाते हों, का भुगतान करते हुए मूल्य का भाग हो। तथापि, सरकार, जब कभी आवश्यकता हो, क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा, यदि अनुरोध किया जाता है, तो उत्पाद शुल्क अथवा करों को लौटाने पर विचार कर सकती है।

6. इस अधिसूचना के तहत प्रदत्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियां, छूट तथा सुविधाएं क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल के हित में मजूर की गई हैं न कि उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत फायदे के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास फेडरेशन तथा रेड क्रीसेंट सोसायटीज किसी व्यक्ति को प्रदत्त उन्मुक्ति को समाप्त कर देगा, यदि उसके विचारानुसार ऐसी उन्मुक्ति से न्याय बाधित होगा और उन्मुक्ति को इस प्रकार समाप्त करना उन प्रयोजनों के प्रतिकूल नहीं होगा जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई है।

7. क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल तथा अंतर्राष्ट्रीय रेड-क्रास फेडरेशन और रेड क्रीसेंट सोसायटीज यह सुनिश्चित करने का हर संभव उपाय करेगा कि इस अधिसूचना के तहत प्रदत्त विशेषाधिकार, उन्मुक्ति, छूट तथा सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं हो और इस प्रयोजनार्थ ऐसे नियम तथा विनियम बनाएगा जिसे वह आवश्यक तथा अनिवार्य समझे। यदि सरकार ऐसा समझती है कि किसी प्रकार का दुरुपयोग हुआ है तो सरकार और अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के बीच विचार-विमर्श किया जाएगा।

8. इस अधिसूचना के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के कारण होने वाले किसी प्रकार के मतभेदों को सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास फेडरेशन एवं रेड क्रीसेंट सोसायटीज के बीच भारत में लागू क्रानूनों के अंतर्गत पारस्परिक विचार-विमर्श से हल किया जाएगा।

2. क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस फेडरेशन एवं रेड क्रीसेन्ट सोसायटीज, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल, सी-1/35, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली - 110016

3. संयुक्त सचिव(यूएनईएस)/ डी सी पी(एफ)/ प्रोतोकॉल विशेष/विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2006

S.O. 1488(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby accords to the Regional Delegation of International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in New Delhi (hereinafter "Delegation" or "Regional Delegation") the following privileges and immunities :

1. The Regional Delegation shall possess legal personality and the legal capacity necessary for the exercise of its functions, including right to sue and be sued under the laws applicable in India.
2. The Regional Delegation and its members regardless of their nationality, on being granted legal status shall:
 - (i) Be immune from any legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity.
 - (ii) Be exempt from taxation in respect of the salaries and emoluments paid to them by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
 - (iii) Be immune from national service obligations.
 - (iv) Be entitled to free of charge, together with their spouses and immediate family members dependent on them, appropriate entry visa.
 - (v) Be immune together with their spouses and relatives dependent on them from alien registration.
 - (vi) Be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable ranks forming part of diplomatic mission to the Government.
 - (vii) Be given together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crises as diplomatic envoys.
3. Indian nationals or the permanent residents in India, working in Regional Delegation, shall not be eligible for any of the immunities and privileges.
4. The Regional Delegation, its assets and other property shall be exempt from customs duties and prohibitions and restrictions as may be the case, in respect of reasonable quantity of articles imported by the Regional Delegation for its official use. The articles imported under such exemption shall not be sold in India except under conditions agreed with the Government of India.

5. The Regional Delegation will not, as a general rule, claim exemption from excise duties or taxes on purchase of movable and immovable property, which form part of the price to be paid when the Regional Delegation is making purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable. However, the Government, whenever required, may consider refund of excise duty or taxes, if requested by the Regional Delegation.

6. The privileges, immunities, exemptions and facilities accorded under this Notification are granted in the interest of the Regional Delegation and not for the personal benefit of the individuals themselves. The International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies shall waive the immunity accorded to any person, if, in its opinion, such immunity would impede the course of justice and the waiver would not prejudice the purposes for which the immunities are accorded.

7. The Regional Delegation and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies shall take every measure to ensure that the privileges, immunities, exemptions and facilities conferred under this Notification are not abused and for the purpose shall establish such rules and regulations as it may deem necessary and expedient. There shall be consultation between the Government and the International Federation should the Government consider that an abuse has occurred.

8. All differences arising out of the interpretation or application of this Notification shall be settled by mutual consultations between the Government and the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies as per laws in India.

[No. D-II/451/12(14)/2006]

P. R. CHAKRAVARTY, Jt. Secy. & Chief of Protocol